भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–08 अप्रैल, 2022

शांतिपूर्ण जन आंदोलनों पर सरकारी दमन का कड़ा विरोध-प्रतिरोध करें!
जनयुद्ध में बढ़-चढ़कर शामिल होवें, जन राज्यसत्ता को मजबूत बनावें!

विगत दो साल से भी ज्यादा समय से अपनी जायज मांगों को लेकर जारी बस्तर संभाग के आदिवासी जन आंदोलनों पर केंद्र की भाजपा सरकार के दिशानिर्देश पर राज्य की भूपेश बघेल सरकार द्वारा चलाए जा रहे तीव्र दमन की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती है. साथ ही दमन का विरोध करने राज्य एवं देश के प्रगतिशील–जनवादी बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार संगठनों से अपील करती है. दमन का डटकर मुकाबला करते हुए आंदोलनों को और उग्र बनाने आंदोलनरत जनता का आह्वान करती है.

यह सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में मूल कानून के अनुरूप पेसा नियमों को लागू करने, ग्रामसभाओं की अनुमति के बगैर बैठाए गए पुलिस, अर्धसैनिक बलों के कैंपों के खिलाफ, बस्तर में नरसंहार बंद करने, सारकेनगुडा, एड्समेट्टा, तिम्मापुरम–मोरपल्ली–ताडिमेट्ला (टीएमटीडी) के मामलों में सरकारी न्यायिक जांच आयोगों की रिपोर्टों पर अमल करते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों व जवानों पर कार्रवाई करने, आमदाई, रावघाट, तरालमेट्टा, पिट्टोडमेट्टा(नंदराज पहाड़) खनन परियोजनाओं, बोधघाट बांध परियोजना, दल्ली–रावघाट–जगदलपुर रेल लाइन संबंधित एमओयु रद्द करने सहित पुल–पुलियाओं, सड़कों के निर्माण के विरोध में एवं अन्यान्य मांगों को लेकर पिछले दो साल से भी अधिक समय से कइयों जगह लाखों जनता शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही है. इनमें से सिलंगेर, पूसनार, वेच्चाघाट, गोंपाड, पूसगुप्पा जैसे संघर्ष तो पिछले कई महीनों से जारी हैं. इन आंदोलनों को राज्य ही नहीं, देश–दुनिया से समर्थन प्राप्त है.

इसके बावजूद राज्य सरकार जनता की मांगों को पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठायी. उल्टे सड़कों, पुल–पुलियाओं का निर्माण बेरोकटोक जारी है. नए–नए कैंपों को बैठाया जा रहा है. इतना ही नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलनों को क्रूर दमन के जरिए खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है. कई आंदोलनकारियों को झूठे केसों में फंसाकर जेलों में बंद किया गया है. कइयों की बेदम पिटाई की गयी. सुकमा, दंतेवाडा, बीजापुर जिलों के नाहोड, पूसनार, गोंपाड धरना शिविरों पर पाशविक हमले करके पुलिस ने शिविरों को ध्वस्त किया, जला दिया, धरनारत लोगों के कपड़े सहित कई सामनों को जला दिया, कीमती सामानों को लूटा, आंदोलन करने से जान से मारने की धमकियां दी. अपनी जायज मंगों को लेकर आंदोलनरत आदिवासी जनता पर नारायणपुर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया जिसमें कइयों को गंभीर चोटें आयीं. पुलिस कैंपों वाले गांवों तथा आस–पास के गांवों की महिलाओं, युवतियों, नाबालिग लड़कियों को घरों, खेतों एवं तालाबों से उठा ले जाना, अत्याचार करना आदि से जनता काफी परेशान है.

दूसरी ओर पुलिस, सीआरपीएफ अपनी बंदूकों के बल पर ग्रामीणों को इकट्ठा करके सिविक एक्शन प्रोग्राम के नाम पर उन्हें झूठन के तौर पर चिल्हर सामान बांट रहे हैं. इस तरह जनता के एक तबके को अपने पक्ष में आकर्षित करना चाहती है. यह एक हाथ में डंडा मारकर दूसरे हाथ में गाजर थमाने की नीति है जिसका मजबूती से विरोध करने की जरूरत है.

राज्य की वर्तमान कांग्रेस सरकार अपनी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के ही नक्शेकदम चलते हुए नरसंहारों, झूठी मुठभेड़ों को अंजाम दे रही है. भाजपा शासनकाल के नरसंहारों का तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, तथ्यान्वेषण कमेटियां बनायीं, रिपोर्ताज प्रकाशित की. जबकि सत्तारूढ़ होते ही ताड़बल्ला, सिलंगेर को अंजाम दिया. अब राज्य में भाजपा चूंकि विपक्ष में है, इसलिए वह नरसंहारों के विरोध में मगरमच्छ के आंसू बहा रही है. जन आंदोलनों के समर्थन का ढोंग कर रही है. हमारी पार्टी भाजपा, कांग्रेस पार्टियों के जनविरोधी, कारपोरेटपरस्त, जन दमनकारी स्वभाव व चरित्र को समझने, दोनों का जबरदस्त विरोध करने का आह्वान करती है.

हमारी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी बस्तर की जनता का आह्वान करती है कि वह जन आंदोलनों की हर संभव मदद करें. साथ में इस समझदारी के साथ कि जन आंदोलनों को जनयुद्ध के साथ जोड़कर ही जन राज्यसत्ता को बचाया जा सकता है, मजबूत व विस्तार किया जा सकता है, जन आंदोलनों के साथ–साथ जनयुद्ध में बड़े पैमाने पर शामिल होवें.

विकल्प

(विकल्प)
प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)